

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 29 संख्या: 257

प्रभात

अजमेर, शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

## गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी बॉस्टन के लिए रवाना हो गये

राहुल गांधी बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों व फ्रैन्ड्स ऑफ कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे

**-रेणु मिश्रल-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। राहुल गांधी, जो दिल्ली में यथासंभव कम ही समय गुजारते हैं, गुरुवार शाम अमेरिका के बोस्टन शहर के लिये रवाना हो गये, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने शनिवार, 19 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नैशनल हैरल्ड केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ पेश की गई ईडी की चार्जशीट के विरोध के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

खड्गे ने मीटिंग में सभी एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी, सचिव, अग्रणी संगठनों के प्रमुख तथा विभाग प्रमुख बुलाये हैं।

खड्गे द्वारा बुलाई गई पिछली मीटिंग निराशाजनक रही थी, क्योंकि उसमें कई लोग उपस्थित नहीं हुये थे। अनुपस्थित रहे नेताओं में एआईसीसी महासचिव तथा संगठन-प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल थे, जो राहुल गांधी के दायें हाथ तथा उनके पीछे की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिये बहुत से कांग्रेस नेता उन्हें असली कांग्रेस

■ राहुल की यह अमेरिका यात्रा उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि शनिवार को कांग्रेसाध्यक्ष खड्गे ने राज्यों के प्रभारी, महासचिवों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों आदि की बैठक बुला रखी है।

■ इस बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा नैशनल हैरल्ड के मसले में, सोनिया गांधी व राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है, उसके संदर्भ में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाये।

■ बैठक बुलाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार विरोध के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किये गये थे, वे काफी “फ्लॉप” रहे थे। तथा, कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे थे। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, वे गुजरात में राहुल गांधी के साथ थे।

■ अतः यह अजीबोगरीब बात है, कि, सोनिया गांधी व राहुल गाँधी को मजबूती देने का कार्यक्रम तय करने के लिए आयोजित बैठक में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे।

अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय वे ही लेते हैं तथा खड्गे के निर्णयों को उलट भी देते हैं। यह मीटिंग राहुल गांधी की

## 1950 के दशक के “हिन्दी-चीनी भाई-भाई” के नारे को दोहराना चाहता है चीन

पर, 1950 में भारत भोला, आदर्शवादी सोच से ओत-प्रोत, नया देश था, पर अब परस्थितियां भी बहुत बदल गई हैं

**- सुकुमार साह -**  
**- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**  
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकेत है जो प्रतीकात्मकता, सही समय और राजनीतिक इरादे से भरा हुआ है। भारत की तरफ चीन की हालिया पहल, जैसे वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क में कटौती और सांस्कृतिक निमंत्रण देना आदि के बारे में कहा जा रहा है कि ये पैन्डेमिक के बाद के सामान्य आर्थिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन तथा लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देना है, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे जाएं तो स्पष्ट होता है कि इन पहलों में उस बीते युग की गुंज है, जब भारत और चीन ने अपने आपको “हिन्दी-चीनी भाई-भाई” के नारे के तहत, एशियाई भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।

1950 के दशक की शुरुआत में

**जल्द शुरू होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा**

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा को शर्तें और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा

■ भारत और चीन के बीच इस संबंध में चल रही तकनीकी वार्ता पूरी हो गई है। जल्दी ही नोटिस जारी कर घोषणा की जा सकती है।

कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है। यह पृष्ठ जाने पर कि लद्दाख में डेमचोक के रास्ते से कैलाश मानसरोवर (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

**-सुकुमार साह-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस महीने के आरम्भ में रैसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत की, तो वैश्विक बाजारों में कई व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 से 125 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई, जिसका तत्काल विरोध हुआ और बाजारों में उथल-पुथल मच गई। लेकिन इस दुस्साहसी कदम के पीछे जो नाम सबसे प्रमुख था, वह था पीटर नवारो, जो लम्बे समय से व्यापारिक संरक्षणवाद का पर्याय बना हुआ है।

ट्रेड और मैनुफैक्चरिंग के लिए

वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवारो, ट्रंप के आक्रामक व्यापार हस्तक्षेपों के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। प्रशासन की व्यापार नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव न तो नया था और न ही संयोगवश। हार्वर्ड-प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नवारो वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो वैश्विक व्यापार समझौतों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन को आर्थिक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा ने उन्हें ट्रंप की आर्थिक टीम में ऊंचे स्थान तक पहुंचाया, जहाँ उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़े बदलाव किए।

नवारो की विचारधारा की जड़ें

■ नवारो का चिन्तन है, कि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में “टैरिफ” की भूमिका अनुचित व्यापारिक तौर तरीकों को रोकने में बहुत महत्व रखती है।

■ साथ ही नवारो के चिन्तन के अनुसार टैरिफ लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ती है।

■ नवारो, अपनी इस सोच के कारण, ट्रम्प प्रशासन में काफी लोकप्रिय हैं, तथा ट्रम्प प्रशासन के इकॉनमिस्ट नैशनलिस्ट उन्हें अपना वैचारिक गुरु मानते हैं।

■ पर, मुख्यधारा के इकॉनमिस्ट को नवारो का सोच बहुत “सिम्पलिस्टिक” (साधारण व भावनाओं से प्रेरित) लगा, तर्क व आंकड़ों पर आधारित कम नज़र आया।

उन्के 2011 की किताब “डेथ बाय चाइना” से जुड़ी हैं, जिसमें उन्होंने चीन

अब तक किसे व कितनी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति दी गई

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति क्या थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश कुमार मनजीत देवड़ा को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।

■ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को शपथ पत्र के द्वारा जानकारी देने के निर्देश दिये।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी मापदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया। वह करीब डेढ़ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक उसे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके चलते उसका प्रवेश रद्द हो सकता है और उसका वीजा भी समाप्त किया जा सकता है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से योजना को संपूर्ण जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित, वक्फ विधेयक पर “स्टे” नहीं दिया

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, संकेत दिये थे, कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों को “स्टे” करने की सोच रहा है

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन पहले ऐसे संकेत दिये थे कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे दे सकता है, लेकिन गुरुवार को न्यायालय ने वक्फ कानून में हाल ही में किये गये कुछ बदलावों पर स्टे नहीं दिया, क्योंकि केन्द्र ने अदालत को आश्वासन दे दिया कि वक्फ बोर्डों तथा कार्डसिलों में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूज़र के रूप में घोषित या रजिस्टर्ड सम्पत्तियों को निर्दिष्ट (डिनेटिफाई) नहीं किया जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केन्द्र की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आशय के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया।

संक्षिप्त-सी सुनवाई के बाद, बेंच,

■ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों के समुख तर्क रखा कि, “प्राइमा फेसिया” रीटिंग के बाद, संशोधित वक्फ विधेयक के प्रावधानों को “स्टे” करना उचित नहीं होगा।

■ मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, पर यह वादा भी मांगा सरकार से कि वक्फ बोर्ड में नवनियुक्तियां, वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित करना, आदि कार्यवाही नहीं होगी सरकार की ओर से।

■ सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर कि, सात दिनों में सरकार पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपना जवाब पेश करेगी, तथा तब तक वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का “स्टे” नहीं दिया।

जिसमें जस्टिस संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

ने कहा कि “प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।” “उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित

के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

ने कहा कि “प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।” “उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित

का मूल दर्शन, जो व्यापारिक घाटा कम करने, विदेशी व्यापार में जोड़-तोड़ का मुकाबला करने और अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने पर आधारित है, ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 में घोषित साहसी नीति का वैचारिक आधार बना।

अब यह सिर्फ़ एकैडमिक रुख नहीं रहा है। नवारो ने न केवल टैरिफ का समर्थन किया। बल्कि इस टैरिफ नीति के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी और इसके पक्ष में बहुत ज्यादा मुखर भी थे। फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में नवारो ने इसे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रक्रिया के खिलाफ सुधारात्मक उपाय बताते (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

■ दुलत कई वर्षों तक कश्मीर में भारत सरकार की इंटैलिजेंस एजेन्सी ‘रॉ’ के मुखिया के रूप में कार्यरत रहे थे, तथा डॉ. फारुख अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी बनने से लेकर अब तक, बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं।

■ उनका (दुलत साहब का) शुरू से मानना है कि, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, अपने पिता कि भांति पूर्णतया भारत के प्रबलतम समर्थक रहे हैं। पर शेख अब्दुल्ला व डॉ. फारुख में एक प्रमुख फर्क था। शेख अब्दुल्ला, कई मसलों पर दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आन्दोलनरत भी रहे, तथा कई साल जेल में भी रहे, पर डॉ. फारुख अब्दुल्ला सदा केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते रहे हैं।

■ शायद, दुलत साहब अपनी किताब में डॉ. अब्दुल्ला के इस व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करने जा रहे थे।

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

प्रावधानों के धारा 9 तथा 14 के तहत कार्डसिल तथा बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, चाहे अधिसूचना के जरिये घोषित किया गया हो, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चिन्हित नहीं किया जायेगा, और न उसका स्वरूप या प्रकार ही बदला जायेगा। हमने यह कथन रिकॉर्ड पर ले लिया है। सात दिन के अन्दर, प्रतिवादियों की ओर से जवाब/काउन्टर ऐफिडेविट पेश हो जाना चाहिये। उसके बाद, पाँच दिन के अन्दर उसका जवाब पेश हो जाना चाहिये।”

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है इसमें वे प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बोर्ड और कार्डसिल के गैर मुस्लिमों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

अजमेर दरगाह विवाद पर सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर, 17 अप्रैल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

■ गत नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को पूजा स्थल विवाद पर कार्यवाही जारी नहीं रखने के निर्देश दिये थे। दिसम्बर में अदालत को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी पर निचली अदालत ने कार्यवाही जारी रखी।

गई है। खादिमों की संस्था, अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवाजी ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK







# काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव और शराब के नशे में तोड़ी मूर्ति



बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाल कोठी सब्जी मंडी में शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

था और काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव में चल रहा था। इसके

चलते 11 अप्रैल की सुबह ही शराब का नशा कर लिया और फिर वह लाल

कोठी सब्जी मंडी में शिव जी के मंदिर में चला गया। वहां बैठ कर वह एक बार जोर जोर से रोने लगा और फिर भगवान की तरफ देख कर कहने लगा कि तुम्हारा कोई बुधा नहीं किया और फिर भी आप मुझसे नाराज रहते हो। इसके बाद मंदिर में रखी एक टाईल से शिव जी व पास में लगी भगवान की मूर्तियों को तोड़ कर दुर्गापुर चल गया। जहां से ट्रेन में बैठकर गांव चला गया था जहाँ से वापस ही जयपुर आ गया था और अपने जानकार के पास शराब पीने चला गया। जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व,सीएसटी व थाना बजाज नगर की टीमो का गठन किया गया। जहां गठित टीम के सदस्यों ने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए

- शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का मामला
- पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

ट्रेडिशनल पुलिसिंग करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो एक संदिग्ध आदमी मंदिर के अन्दर से निकलता हुआ नजर आया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश के लिए घटनास्थल से अलग-अलग रुटों पर अलग-अलग टीमों को टास्क दिया गया तथा टीमों द्वारा लगातार 6 दिन तक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की वीडियो फुटेज चेक करते हुए संदिग्ध आरोपी का रूट मैप तैयार किया जाकर सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे गये तथा आस पास मंडी में काम करने वाले मजदूरों, टोंक फाटक पर मजदूरों की चौकटी पर संदिग्ध हुलिया के व्यक्ति के तस्वीर दिखाई तथा अंग्रेजी शराब ठेकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो संदिग्ध हुलिया का व्यक्ति की पहचान की गई। तत्पश्चात टीम के सदस्यों ने दिन रात शराब ठेकों के आसपास रेकी करके निगरानी रखते हुए आरोपी राजेश राव को गिरफ्तार किया गया।

## संस्कृत गौरव के संवाहक बनें विद्यार्थी : बिरला

- जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह

दर्शन के माध्यम से विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है और ऐसे समय में संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जब विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में संस्कृत पर शोध हो रहे हैं, तब भारत में भी इसे नवाचार, तकनीक और डिजिटल युग से जोड़ना समय की मांग है। विश्वविद्यालय द्वारा योग को

तकनीकी दृष्टिकोण से पढ़ाने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की गई। बिरला ने यह भी स्मरण कराया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेश्व भैरोंसिंह शेखावत ने पूज्य नारायणदास महाराज की प्रेरणा से किया था। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

## जयपुर फुट की निर्माता संस्था ने इस वर्ष डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया

जयपुर। जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने वर्ष 2024-25 में देशभर में लगभग डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया। समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता ने बताया कि वर्ष 2024-24 में कुल 149231 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कैलीपर्स, व्हील चेयर, तिपहिया, ट्राइ साइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराये। समिति इस वर्ष में जयपुर और देश भर के अपने 34 केंद्रों की मार्फत 43722 कृत्रिम पैर (जयपुर फुट) दिव्यांगों को लगाकर उन्हें चलने फिरने योग्य बनाया। डी.आर.मेहता ने कहा कि विश्व की कोई भी विकलांग पुनर्वास संस्था एक वर्ष में जहां चार हजार विकलांगों का पुनर्वास नहीं कर पाती, वहीं समिति ने एक लाख 49 हजार

### सांगानेर खुली जेल से दो बंदी भागे

जयपुर। मालपुरा गेट थाना इलाके में स्थित सांगानेर खुली जेल से दो बंदियों के भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फरार कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रोल-कॉल करने पर जेल प्रशासन को बंदियों के फरार होने का पता चला। जेल प्रशासन की ओर से फरार कैदियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि डॉ. संपूर्णानंद बंदी खुला शिविर के जेल प्रहरी ने मामला दर्ज करवाया है कि फरार कैदी सद्दाम और मोहनलाल हैं। जो सांगानेर खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दण्डित बंदी सद्दाम और मोहन लाल रोल कॉल के समय मौजूद नहीं मिले। दोनों कैदियों को उनके आवास और आस-पास तलाश किया। लेकिन वह गायब मिले। उसका मोबाइल नंबर भी रिवच ऑफ फाइंड की संख्या से कहीं अधिक है। उन्होंने बताया कि समिति अपनी स्वर्ण जयंती पर हर विकलांग का पुनर्वास करने का प्रयास करेगी।

## चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर एक्वाडक्ट बनेगा



- निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिली स्वीकृति
- नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र होगा शुरू

नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए आवश्यक 328 हेक्टेयर भूमि अवापित का अवाई शीघ्र जारी कर प्रभावितों को जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। एक्वाडक्ट निर्माण में वन्यजीव

सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। साथ ही, 24.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। कार्यस्थल पर संबंधित एजेंसी द्वारा कैम्प स्थापित कर लिया गया है। चम्बल एक्वाडक्ट के लिए कास्टिंग यार्ड, बैंचिंग प्लांट इत्यादि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यों की मजबूती के लिए सर्वे और अनुसंधान पूर्ण कर डिजायन/ड्राइंग तैयार कर ली गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित पीकेसी का कार्य प्रगतिरत है। इसमें एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य समयबद्ध और मजबूती से पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चिता की जाएगी।

## नवीन आवासीय योजनाओं को लेकर मण्डल में तैयारियाँ तेज



आवासन मंडल की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बैठक ली।

- कार्यप्रगति की समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- जयपुर में भी आयेगी विभिन्न आय वर्ग के लिए आवासीय योजना

तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अहम बैठक ली। डॉ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की संसानुरूप आवासन मण्डल आम जन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि

इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉ शर्मा ने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश एवं घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमें हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें।

उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है

बैठक में सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

### अधिकारी अधिक-से-अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को मंत्रालय भवन में दोनों विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी निरीक्षण करें एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष नवंबर से संपन्न लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के द्वारा अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने से सरकार को जो अन्न की बचत होगी वह गरीब का निवाला बनेगा। इससे बड़ी गरीब की सेवा नहीं हो सकती। इस अभियान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सलाह में न्यूनतम 3 दिन आवश्यक रूप से फील्ड में दौरा कर निःशुल्क राशन की दुकानों का निरीक्षण करें।

### मंदिरों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के दौरान मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए : दिया कुमारी



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिल्डिंग एवं स्पेशल स्कीम खंड के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने, समय पर साथ कार्य पूर्ण करने एवं मेंटेनेंस की प्रभावी योजना तैयार करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देने के साथ भवन निर्माण में सौर ऊर्जा के

उपयोग तथा जल संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता देने के दिशा-निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त, मंदिरों एवं अन्य विरासत स्थलों के जिर्णोद्धार कार्यों के दौरान उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर और अन्य स्थल वर्षों पहले स्थानीय सामग्री एवं स्थानीय शिल्प कला का उपयोग करके बनवाए गये हैं। इनकी मरम्मत के दौरान उसी सामग्री एवं शिल्प कला का ध्यान रखा जाये।

## ‘हीट वेव एक्शन प्लान की केन्द्र व राज्य सरकार जानकारी दें’ हाईकोर्ट ने गत वर्ष मई में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे, पर दस माह बाद भी कोई प्लान नहीं बना

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हीट वेव व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय आपदा प्रबंधन और राज्य के सीएस, एसीएस गृह व एसीएस वित्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने सीएस को निर्देश दिए हैं कि वे हीट एक्शन प्लान व स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वित के लिए सभी विभागों को साथ लेकर एक समन्वय समिति बनाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि समान मामले में गत वर्ष मई माह में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया और सरकार को निर्देश जारी किए, लेकिन करीब दस माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। यहां तक की सदकों पर पानी की छिड़काव करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही सड़कों पर छाया स्थल विकसित किए गए। इसके अलावा लू से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट, आम पन्ना आदि का वितरण भी नहीं किया गया। सरकार की ओर से अभी तक हीट एक्शन प्लान तक नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा कि प्रदेशवासियों के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता और अदालत आंख बंद कर नहीं रह सकती है।

जयपुर। 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हीट वेव व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय आपदा प्रबंधन और राज्य के सीएस, एसीएस गृह व एसीएस वित्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने सीएस को निर्देश दिए हैं कि वे हीट एक्शन प्लान व स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वित के लिए सभी विभागों को साथ लेकर एक समन्वय समिति बनाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि समान मामले में गत वर्ष मई माह में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया और सरकार को निर्देश जारी किए, लेकिन करीब दस माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। यहां तक की सदकों पर पानी की छिड़काव करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही सड़कों पर छाया स्थल विकसित किए गए। इसके अलावा लू से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट, आम पन्ना आदि का वितरण भी नहीं किया गया। सरकार की ओर से अभी तक हीट एक्शन प्लान तक नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा कि प्रदेशवासियों के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता और अदालत आंख बंद कर नहीं रह सकती है।

अदालत ने कहा कि राजस्थान का तापमान दिन-प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। आगामी ग्रीष्म काल जन स्वास्थ्य, लू और हीट स्ट्रोक के मामले एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राज्य सरकार को हीट वेव और हीट स्ट्रोक से मुक्त रखने के लिए सभी स्तरों पर उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। अदालत ने केन्द्र सरकार के एएनजी आरएल रस्तोगी, राज्य के एएजी और अन्य वकीलों को कहा है कि वे इस मामले में अदालत को सहयोग करें।

### हीटवेव को देखते हुए दवाओं की हो समुचित उपलब्धता : नेहा गिरी

- अनियमितता पर इंगरपुर जिला औषधि भण्डार के प्रभारी अधिकारी को नोटिस

का गहन परीक्षण कर अनुमोदित आपूर्तिकर्ता फर्मों को क्रय आदेश जारी किये जाने एवं शीघ्र आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों से समन्वय किया जाए। समस्त प्रभारी अधिकारी फीडबैक मात्रा का परीक्षण कर ही क्रय आदेश मात्रा भिजवाये, जिससे औषधियों की कमी एवं अधिकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रबंध निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक मांग में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, इंगरपुर एवं संबंधित चिकित्सा संस्थानों का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भण्डार गृहों में शत-प्रतिशत औषधियां उपलब्ध करवा कर रोगियों को राहत पहुंचाई जाए। योजना के सफल क्रियान्वन हेतु समस्त प्रभारी अधिकारी संबंधित जिलों में चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। महंगी औषधियों की सचन मॉनिटरिंग करें तथा इससे संबंधित रिकॉर्ड का संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।







मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोकरण में “रिन्यू पावर” कम्पनी के 1.3 “गीगावॉट पीक” के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जैसलमेर में स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी।

## पोकरण में 1.3 गीगा वॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

### सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को गति मिलेगी-भजनलाल

पोकरण, 17 अप्रैल (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को पोकरण में “रिन्यू पावर” कम्पनी के 1.3 “गीगावॉट पीक” के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा

■ **केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी क्षेत्र में बेहतरनी कार्य किया जा रहा है।**

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से पैदा होने वाली समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल

है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

इससे पहले, हैलीपेड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमन्त्री स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक महंत प्रतापपुरी, छोटसिंह भाटी, “रिन्यू एनर्जी” के सीईओ सुमंत सिन्हा व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित थे।

### 1950 के दशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल. ए. सी.) पर भारी संख्या में सेना तैनात है। कई दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं केवल धीरे-धीरे तनाव कम करने में सफल रही हैं, जबकि सीमा उल्लंघन की घटनाएं और क्षेत्रीय दावे बढ़ नहीं हुए हैं।

मुख्य अंतर यह है कि आज का भारत 1950 के दशक की आदर्शवादी सोच जितना भोला नहीं है। सन् 1962 के कटु अनुभव और हाल ही में 2020 की गलवान घाटी की खूनी झड़प ने नई दिल्ली को यह सिखा दिया है कि प्रतीकात्मकता एवं सांस्कृतिक पहल तभी सार्थक है, जब वे मूलभूत विवादों के समाधान के साथ जुड़ी हों। अब “एशियाई भाईचारे” को पुरानी भाषा का स्थान रणनीतिक सतर्कता ने ले लिया है, और भारतीय नीति निर्माता बीजिंग से आने वाले किसी भी कूटनीतिक संकेत को कहीं अधिक व्यवहारिक और सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण से देखते हैं।

फिर भी, चीन के दृष्टिकोण से देखें तो यह रणनीति उसी पुरानी सोच का अनुसरण करती लगती है कि जनता की सोच को नरम करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, जनसंपर्क और आर्थिक प्रलोभनों का उपयोग करो, लेकिन सीमा पर कठोर रूख बरकरार रखो। यह, द्विपक्षीय संबंधों के माहौल को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को मध्यम करने और स्थिरता के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन वास्तविक रियायतें दिए बिना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस अर्थ में, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का आधुनिक लेन-देन वाला संकरण है, जिसमें 1950 के दशक की मासूमियत, आशावाद और आदर्शवाद नहीं है, और दोनों राष्ट्रों को इतिहास और वास्तविक राजनीति ने बहुत कठोर बना दिया है। नारे भले ही फीके पड़ गए हों, लेकिन अनुसूले विवादों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को छुपाने के लिए “साफ्ट पावर डिप्लॉमसी” का उपयोग आज भी जारी है, जो इस जटिल और असहज रिश्ते की पहचान है।

### अब तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
पेश करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मामले में भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। जिस पर केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी उपस्थित हुए थे।

## कच्चे मकान में आग लगने से भाई-बहन जिंदा जले

### हादसे में झुलसे माँ-बाप चार में से दो बच्चों को ही आग से बाहर निकाल पाये

■ **घायल पिता प्रभुलाल की भाभी के अनुसार, मकान की छत पर झोपड़ी व तिरपाल लगा था। पास में बिजली के पोल पर तार टूट कर छत पर गिरा, जिससे घर में आग लग गई।**

साथ घर के अंदर भागे लेकिन दो ही बच्चों को बाहर निकाल सके। दो बच्चे उनकी आंखों के सामने ही आग में जल गए। माँ-बाप की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी बच्चों को निकालने की कोशिश की लेकिन उन्हें

बचाया नहीं जा सका। हादसे में दो बच्चों, जीनल गमेती (14) और सिद्धार्थ गमेती (8) की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। घायल प्रभुलाल की भाभी गीता बाई ने बताया कि छत पर झोपड़ी और तिरपाल लगा था। पास में बिजली का पोल है जिसका तार छत पर टूट कर गिर गया। जिसके बाद घर में आग लग गई।

थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी या पेट्रोल से लगी है, फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों नाबालिगों के शव का गुरुवार को खेरवाडा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए वहीं मृतक के माता-पिता का इलाज जारी है।

### “राँ” के पूर्व मुखिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
पुस्तक की विषयवस्तु को “निराधार” तथा “गलतियों से भरी” बताया है। फारुक ने कहा, “आगर वे (दुलत) मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो उन्हें यह पुस्तक लिखनी ही नहीं चाहिये थी। उन्होंने रानी एलिजाबेथ की प्रसिद्ध उक्ति को दोहराते

किस को लपेट लिया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है तथा उन्होंने बार-बार असत्य से काम लिया है।

दुलत ने अपनी पुस्तक में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई डॉ. फारुक एवं उमर अब्दुल्ला की मीटिंग का उल्लेख किया है, जो उनके

■ **पर, बात कुछ बिगड़ सी गई, डॉ. अब्दुल्ला के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डॉ. फारुख अब्दुल्ला पर इस मसले पर कई आरोप लगा कर, राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूक रहे हैं।**

■ **हार कर अब्दुल्ला को भी कहना पड़ा, कि अगर दुलत साहब मेरे मित्र हैं, तो उन्हें यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी।**

हुये कहा: “स्मृतियाँ भिन्न हो सकती हैं।”

डॉ. अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर कहा है: “दुलत सदैव एक जासूस रहे तथा उनकी निष्ठा केवल स्वयं के प्रति रही। अपनी पहले वाली पुस्तकों में उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि उन्होंने किस-

अनुसार, संसद में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक के पारित होने से पहले हुई थी। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है, “ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में नैशनल कॉन्फ्रेंस की विधानसभा चुनावों में जीत, 2019 में दी गई उनकी सेवाओं का पुरस्कार था।

### महाराष्ट्र में कक्षा

1 से 5 तक, हिंदी पढ़ाई जाएगी

मुंबई, 17 अप्रैल। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ ना अनिवार्य होगा। यह दो भाषाओं के अध्ययन की प्रथा से अलग है। राज्य के राजनीतिक दल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए।

कक्षा 1 से 5 के लिए तीन-भाषा फॉर्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का एक हिस्सा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढाँचे के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना घोषित की है।

### जल्द शुरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
यात्रा संचालित करने पर बातचीत हो रही है, प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी ही नोटिस आने वाला है और मार्ग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में दोनों देशों के उड्डयन विभागों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है और जैसे ही सहमत बनती है, वैसे ही जानकारी साझा की जाएगी।

भारत में चीन के राजदूत द्वारा एक्स पर पोस्ट में 85 हजार भारतीयों को वीजा देने जाने संबंधी दावे के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब संबंध सामान्य बनाने और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने की बात होगी तो वीजा भी बढ़ेगा।

हालांकि उनके पास इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है।

### ट्रम्प प्रशासन की “रैसिप्रोकल” आक्रामक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
हुए सरकार के लिए राजस्व का संभावित स्रोत बताया। नवरो ने कहा, टैरिफ इस देश के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेंगे, पर हम धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रति बाज़ार की प्रतिक्रिया काफी तीव्र व क्रूर थी। अमेरिकन शेयर बाज़ार गिर गया। व्यापारिक सहयोगी देशों ने जवाबी धमकियाँ दीं। अमेरिका व उसके व्यापारिक मित्रों के बीच बनाव चरम पर पहुँच गया। भारी एवं त्वरित विरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों व अपने ही लोगों के दबाव में आ गए और क्रियान्वयन के 13 घंटे में ही उन्होंने नई टैरिफ नीति के क्रियान्वयन को 90 दिन के लिए टाल दिया। यह निर्णय प्रशासन की आर्थिक टीम की आंतरिक खींचतान का प्रतीक बन गया।

अमेरिका के ट्रैजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बैसेट व अन्य उदारवादी आर्थिक सलाहकारों ने बार-बार चेतावनी दी थी कि आक्रामक टैरिफ नीति ग्लोबल स्लाई चैन में बाधा बन सकती है और अमेरिका में महंगाई का संकट गहरा सकता है। लेकिन नवरो, जो कठोर रुख के हिमायती हैं, पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार आक्रामक रुख पर जोर देते रहे, जबकि इसमें भारी खतरा है।

ट्रंप की ट्रेड नीति पर नवरो की छाप हमेशा विवादास्पद रही है। जहाँ समर्थकों ने स्थापित वैश्विक व्यापार प्रणालियों को चुनौती देने की उनकी तत्परता का समर्थन किया, खासकर बौद्धिक सम्पदा चोरी और जबरन तकनीकी हस्तोत्तरण के मुद्दे पर चीन से टकराव के मामले में। लेकिन उनके आलोचकों, खासकर वे जो खुले बाज़ार

के समर्थक हैं, ने कहा कि नवरो का यकीन आर्थिक प्र्रातियों से प्रेरित है। उन्होंने कहा, व्यापार घाटा अपने आप में नुकसानदेह नहीं होता और संरक्षणवादी उपाय कोमत्तें बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी निर्यात पर प्रतिकार स्वरूप टैरिफ लग सकता है।

अंत में भले ही टैरिफ नीति को देरी व आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पर ट्रंप के ट्रेड एजेंडा पर नवरो का गहरा असर कायम है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी व्यापार की सजा ट्रंप के कार्यकाल की पहचान रही थी, जिसका अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आज भी वैश्विक व्यापार के भविष्य और आपस में जुड़ी हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर ट्रंप के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं।

### उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
धमकी देने का फोन किया और ना ही उनसे कोई मोबाइल या सिम बरामद हुई। वे अन्य आरोपियों से संपर्क में भी नहीं थे, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं रचा है, प्रकरण में झूठा फैसाया गया है। इसके विरोध में लोक अभियोजक लियाकत अली ने कहा कि आरोपियों ने संगठित अपराध कर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी है। जांच में आया है कि जुनैद ने स्वयं के नाम से सिम खरीदकर मोहम्मद अशराफ के साथ मिलकर केन्द्रीय कारागृह में बंद कैदी को सिम मुहैया कराई और अन्य आरोपियों ने इस सिम का उपयोग किया।दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।

रोकी। इसके बाद पुनः जनवरी माह में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत को अवगत कराया।

इसके बावजूद भी निचली अदालत मामले में कार्रवाई जारी रख रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूजा करने के अधिकार के मुद्दे पर सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहीं दावाकर्ता ने बहुत कम कोर्ट फीस के साथ दावा किया है। इसलिए निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने से रोका जाए। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता दावे में पक्षकार नहीं है, ऐसे में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।

## केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
शामिल करने तथा विवादास्पद वक्फ भूमि की स्थिति बदलने के लिए कलैक्टर को दिए गए अधिकारों से संबंधित है।  
साँलिसटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा कि, प्रारंभिक रूप से या कुछ खास भागों को पढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाना अनुचित होगा। उन्होंने कहा, हम आपको कानून के इतिहास में ले चलते हैं। लगभग 100 साल पहले 1923 में यह कानून बना था फिर 1935 में फिर 1954 में बना, उसके बाद 1987 में संशोधन हुआ। फिर 1995 में एक समिति का सुझाव आया और संशोधन हुआ। इसी बीच हम सरकार व संसद के रूप में जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। हमें लाखों लोगों ने अपने सुझाव, जिनके आधार पर कुछ प्रावधान

किए गए हैं। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए गाँव के गाँव वक्फ के रूप में ले लिए गए हैं। लोगों की प्राइवेट सम्पत्ति भी वक्फ के रूप में ले ली गई है और जब वे मुद्दे हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा ये विवादास्पद सवाल हैं, इस पर कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ऐसा मामला है जिसके कोर्ट को सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को जमीन पर व सम्पत्ति पर उनके अधिकार को प्रभावित करेगा। जब जस्टिस संजय कुमार ने कहा, कोर्ट अभी निर्णय नहीं ले रहा तो मेहता ने कहा, लेकिन आप बहुत गंभीर और कठोर कदम उठा रहे हैं। आंशिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्टे लगाकर। मेहता ने कहा, मेरा निवेदन है कि

मुझे एक सप्ताह दिया जाए मैं वादा करता हूँ, एक सप्ताह के भीतर मैं कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दूँगा। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह के विचार किया जा सके। सीजेआई खन्ना ने कहा, “हो सकता है, कुछ विसंगतियाँ हों, पर हमने कहा है कि कुछ सकारात्मक बातें हैं मैं स्पष्ट कर दूँ कि किसी ने कहा था कि पूर्ण रोक लगाई जाए। हमने कब नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पर इसी के साथ हम नहीं चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। हम नहीं चाहते कि अभी जो स्थिति है, उसमें इतना बदलाव कर दिया जाए कि उसका प्रभाव भारी पड़े। इसमें कुछ प्रावधान हैं जैसे वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। हम

इस पर स्टे नहीं लगा रहे हैं। आप का कहना सही है कि कोर्ट का मुख्य नियम है कि वे किसी भी कानून पर प्रारंभिक अवस्था में रोक नहीं लगा सकते हैं। पर एक अन्य नियम यह भी है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। मेहता ने फिर कोर्ट को “वक्फ बाय यूजर” के प्रावधान पर और वक्फ बोर्ड व काउन्सिल्स में नियुक्तियों के संबंध में भरोसा दिलाया।

### गुरुवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
वास्तविक बाँस हैं तथा वे ही यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी एजेंसी किस नेता के पीछे पड़ेगी।

UP TO **50% OFF** ON MAKING CHARGES\* THIS SEASON

KALYAN SPECIAL | GOLD RATE ₹8815\*\*\* | SAVE ₹225\*\* | MARKET | GOLD RATE ₹9040\*\*\*

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: AJMER ROAD - CRM NO.: 73405 61233, VAISHALI NAGAR - CRM NO.: 91158 03333 | UDAIPUR - CRM NO.: 88756 78133  
JODHPUR - CRM NO.: 94133 12103 | KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933  
SRI GANGANAGAR - CRM NO.: 74249 65433 | AJMER - CRM NO.: 77424 13156

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON

BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET